

**भाग -I****हरियाणा सरकार**

विधि तथा विधायी विभाग

**अधिसूचना**

दिनांक 8 मार्च, 2018

**संख्या लैज. 33/2017-** दि हरियाणा विश्वकर्मा रिकल यूनिवर्सिटी (ऑमेन्डमेन्ट) ऐकट, 2017, का निम्नलिखित हिन्दी अनुवाद हरियाणा के राज्यपाल की दिनांक 26 फरवरी, 2018 की स्वीकृति के अधीन एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है और यह हरियाणा राजभाषा अधिनियम, 1969 (1969 का 17), की धारा 4-के खण्ड (क) के अधीन उक्त अधिनियम का हिन्दी भाषा में प्रामाणिक पाठ समझा जाएगा।

**2017 का हरियाणा अधिनियम संख्या 30****हरियाणा विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2017****हरियाणा विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय अधिनियम, 2016,**

को आगे संशोधित करने के लिए

**अधिनियम**

भारत गणराज्य के अडसठवे वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

1. यह अधिनियम हरियाणा विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2017, कहा जा सकता है। संक्षिप्त नाम।
2. हरियाणा विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय अधिनियम, 2016 (जिसे, इसमें, इसके बाद, मूल अधिनियम कहा गया है), की धारा 7 में, खण्ड (क) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—
  - (फ) धारा 35 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, निदेशक, प्रधानाधार्य, विश्वविद्यालय के अध्यापक, गैर-अवकाश शैक्षणिक कर्मचारिवृन्द, अध्यापनेत्तर कौशल, प्रशासकीय तथा लिपिकीय कर्मचारिवृन्द के पद और ऐसे अन्य पद, जो विश्वविद्यालय द्वारा अपेक्षित हों, को सृजित करना तथा नियुक्ति के निवन्धन तथा शर्ते विहित करना ;
  - (ब) स्थापना करना, बनाए रखना तथा प्रबन्ध करना, जब-जब आवश्यक हो,—
    - (क) ज्ञान संसाधन केन्द्र ;
    - (ख) विश्वविद्यालय विस्तार बोर्ड ;
    - (ग) सूचना व्यूरो ;
    - (घ) रोजगार मार्गदर्शन व्यूरो ;
    - (ङ) रसायन विज्ञान व्यूरो ;
  - (म) सभी ऐसे कार्य करना, जो विश्वविद्यालय के सभी या किन्हीं उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आवश्यक, आनुषांगिक या सहायक हों।”।
3. मूल अधिनियम की धारा 12 की उप-धारा (3) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-धारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—
 

“(3) राज्य सरकार, कुलपति की अवधि की समाप्ति से तीन मास पूर्व, कुलाधिपति का एक नामनिर्देशित तथा कार्य परिषद् के दो नामनिर्देशितियों को भिलाकर चयन समिति गठित करेगी, जो वर्णनुक्रम में, कम से कम तीन नामों का कोई पैनल तैयार करेगी, जिसमें से कुलाधिपति, राज्य सरकार की सलाह पर, कुलपति नियुक्त करेगा। कुलपति की सेवा के निवन्धन तथा शर्ते, राज्य सरकार की सलाह पर, कुलाधिपति द्वारा निर्धारित की जाएंगी।”।
4. मूल अधिनियम की धारा 18 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—
 

“18. कौशल परिषद्.— (1) कौशल परिषद् विश्वविद्यालय का प्रधान शैक्षणिक निकाय होगा और इस अधिनियम, परिनियमों तथा अध्यादेशों के उपबंधों के अधीन रहते हुए, विश्वविद्यालय की सभी शैक्षणिक तथा कौशल प्रशिक्षण नीतियों का समन्वय करेगी तथा उन पर सामान्य पर्यवेक्षण करेगी।

2016 के हरियाणा अधिनियम 25 की धारा 7 का संशोधन।

2016 के हरियाणा अधिनियम 25 की धारा 12 का संशोधन।

2016 के हरियाणा अधिनियम 25 की धारा 18 का प्रतिस्थापन।

(2) कौशल परिषद् का गठन, इसके सदस्यों की पदावधि तथा इसकी शक्तियां तथा कृत्य ऐसे होंगे, जो विहित किए जाएं।"

2016 के  
हरियाणा  
अधिनियम 25  
की धारा 24  
का संशोधन।

**5.** मूल अधिनियम की धारा 24 के खण्ड (ज) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थातः—

- "(ज) पाठ्यक्रम के प्रारम्भ से प्रथम तीन वर्षों के लिए आर्थिक सहायता प्राप्त पाठ्यक्रमों को बनाए रखना;
- (झ) शिक्षुता कार्यक्रम जिसमें कार्य अध्ययन कार्यक्रमों को बढ़ावा देने के लिए निधि है, प्रारम्भ करना तथा छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करना;
- (ए) विश्वविद्यालय के समस्त निष्पादन के प्रति सभी परिषदों की जिम्मेवारियों को परिभाषित करना ताकि विश्वविद्यालय की उन्नति तथा विकास की दिशा में तीव्रता लाई जा सके;
- (ट) विश्वविद्यालय तथा संबद्ध महाविद्यालयों के छात्रों की रैगिंग की रोकथाम के लिए क्रियाविधि;
- (ठ) महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 (2013 का केन्द्रीय अधिनियम 14) के उपबन्धों के अनुसार विश्वविद्यालय अधिनियम के अध्यापकों, कर्मचारियों, विश्वविद्यालय तथा संबद्ध महाविद्यालयों के छात्रों के यीन शोषण के लिए रोकथाम, शिकायतों को दूर करने तथा शारित लगाने के लिए क्रियाविधि;
- (ड) सभी अन्य मामले जो इस अधिनियम अथवा परिनियमों द्वारा किए जाने हैं अथवा अध्यादेशों द्वारा उपबन्धित किए जा सकते हैं।"

निरसन तथा  
व्याकृति।

**6.** (1) हरियाणा विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2017 (2017 का हरियाणा अध्यादेश संख्या 3), इसके द्वारा, निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या की गई कोई कार्रवाई, इस अधिनियम के अधीन की गई बात या की गई कार्रवाई समझी जाएगी।

कुलदीप जैन,  
सचिव, हरियाणा सरकार,  
विधि तथा विधायी विभाग।